[2021] 12 एस. सी. आर.103

गीता मिश्रा

बनाम

सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7919/2021)

16 नवंबर, 2021

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जेजे.]

सेवा कानूनः अंशदायी भविष्य निधि योजना- विश्वविद्यालय द्वारा जारी योजना की प्रयोज्यता- तत्काल मामले में, व्याख्याता के रूप में नियुक्त अपीलार्थी के पति की सेवा के दौरान 24.2.1995 को मृत्यु हो गई- सेवा के दौरान उसने अंशदायी भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना था- उनकी मृत्यु के बाद, सभी सेवानिवृत्ति लाभों का विकल्प के अनुसार निपटान किया गया और विकल्प के अनुसार भुगतान किया गया- इसके बाद, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक योजना शुरू की, जो 1.4.1972 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत हुए उन्हें योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार "नए विकल्प" का उपयोग करने के लिए "एक और मौका" दिया गया-मृतक कर्मचारी की पत्नि-अपीलार्थी ने योजना का लाभ उठाने के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधिपति ने योजना का लाभ उठाने की स्वीकृति दी- हालाँकि, खंड पीठ ने एकल न्यायाधिपति के आदेश को रद्द कर दिया- अपील में, अभिनिर्धारित किया- योजना के तहत, ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और 1.4.1972 को या उसके बाद सेवानिवृत हुआ था, लेकिन विकल्प का उपयोग करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, तो परिवार को नियमों और शर्तों के अधीन "नए विकल्प" का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है-

क्योंकि अपीलार्थी के पति ने अपनी मृत्यु से पहले ही विकल्प का उपयोग कर लिया था, प्रचलित योजना के तहत सभी लाभ परिवार के सदस्यों को प्राप्त हुए थे- इसलिए, अपीलार्थी को एक बार और लाभ प्राप्त करने के लिए "नए विकल्प" का उपयोग करने का अधिकार नहीं था- हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

अपील खारिज करते हुए**, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:**

योजना की शर्त संख्या **5** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक कर्मचारी**,** जो विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है**,** उसकी **1.4.1972 को** या उसके बाद अपने विकल्प का प्रयोग करने से पहले मृत्यु हो गई है**,** तो उसका परिवार नए विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र होगा**,** जिससे उन्हें नियमों और शर्तों के अधीन एक और मौका मिलेगा। अपीलार्थी के पति **ने** अपनी मृत्यु से पहले इस विकल्प का प्रयोग **कर लिया था**। प्रचलित योजना के तहत उपयोग किए जाने वाले विकल्प के संदर्भ में सभी लाभ परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। उक्त आकस्मिकता में**,** योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार**,** अपीलार्थी को फिर से विकल्प का उपयोग करने के लिए एक और अवसर का लाभ उठाने के लिए एक नए विकल्प का उपयोग करने का अधिकार नहीं था। **[**पैरा **5,6] [107-**सी**-**ई**]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील संख्या 7919/ 2021.

एल. पी. ए. सं. 123/2016 में झारखंड उच्च न्यायालय रांची के दिनांकित 29.10.2018 के निर्णय और आदेश से।

आदित्य शंकर प्रसाद, समीर कुमार, शाहरुख अहमद, साहिल चौधरी, मंदीप बैसला, अपीलार्थी के अधिवक्तागण।

राजीव सिंह, सामंत सिंह, कुमार अरुनीश सिंह, अभिषेक विक्रम, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय प्रदत्त किया गया -

जे**.** के**.** माहेश्वरी**, न्यायाधिपति**

1. अवकाश अनुदत्त की गयी ।

2. एल.पी.ए. संख्या 123/2016 में झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 29.10.2018 के आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी ने इस अपील में इस आदेश को रद्द करने और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 4441/2010 में पारित दिनांकित 5.2.2016 के आदेश को बहाल करने के अनुरोध के साथ दायर किया है ।

3. वर्तमान मामले में विवाद प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या एसकेयू/एसीसी/202/98 दिनांक 30.7.1998 (संक्षेप में "योजना") द्वारा जारी की गई योजना की प्रयोज्यता के लिए सीमित है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि जो कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा से 1.4.1972 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, यदि विकल्प का उपयोग करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके पास उक्त योजना में निर्दिष्ट एक नए विकल्प का उपयोग करने का एक और मौका है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि उक्त योजना द्वारा "नए विकल्प" का उपयोग करने के लिए "एक और मौका" दिया गया था और इसी तरह के मामलों में, 27.06.2009 को निर्णित डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 4452/ 2007 और डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 4453/ 2007 में वही लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया गया था। उक्त मामले में, एल.पी.ए. संख्या 395/2009 और 397/ 2009 को खारिज कर दिया गया। इसलिए, अपीलार्थी को योजना के लाभ का हकदार ठहराया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा एलपीए दाखिल करने पर, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को यह अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त कर दिया गया कि योजना का लाभ केवल उन लोगों पर लागू होता है, जिन्होंने इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि पर मृत्यु से पहले अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया है। वर्तमान मामले में, विकल्प का प्रयोग अपीलार्थी के पति द्वारा कर लिया गया था। इसलिए,

अपीलार्थी योजना के तहत दूसरे विकल्प का उपयोग करने का हकदार नहीं था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को लाभ नहीं देकर एक त्रुटि की। उक्त आदेश का विरोध करते हुए, मृतक कर्मचारी की पत्नी ने यह अपील दायर की है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के बाद, यह पता चलता है कि अपीलार्थी के पति को रसायन विज्ञान विभाग, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे रीडर के पद पर पदोन्नत किया गया था। 24.2.1995 को नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सेवा के दौरान, अपीलार्थी के पति ने अंशदायी भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना था। विकल्प के अनुसार, वेतन से 10 प्रतिशत की दर से नियमित कटौती की जा रही थी। मृत्यु के बाद, सभी सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान किया गया और उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार भुगतान किया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक योजना 30.7.1998 को शुरू की, जो योजना में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार "नए विकल्प" का प्रयोग करने के लिए "एक और मौका" देने के लिए 1.4.1972 को या उसके बाद विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। योजना का खंड 5 वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जिसे इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"सिधु कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

पत्र सं. केयू/एसीसी/202/98 तिथि 30.07.98

प्रेषक :

कुलसचिव

सिधु कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

प्रेषिती : (1) प्रशासनिक प्रमुख, पी. जी. केंद्र, दुमका

(2) बी. एस. के. महाविद्यालय, बरहरवा और मिल्लत महाविद्यालय, परसा को छोड़कर सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका के अंतर्गत आने वाले घटक महाविद्यालयों (गोड्डा महाविद्यालय, गोड्डा) के सभी प्राचार्य।

विषयः सेवानिवृत्ति लाभ कानूनों के अनुदान के तहत नए विकल्प का प्रयोग।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि कुलपति ने विभाग को आदेश दिया है कि सिद्धु कान्हू विश्वविद्यालय और इसके घटक महाविद्यालयों के सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी जो 1.4.78 से पहले विश्वविद्यालय/घटक महाविद्यालयों की सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा, यदि वे चाहें तो निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत सेवानिवृत्ति लाभ प्रतिभूतियों के अनुदान की किसी भी वैकल्पिक योजना के लिए एक नया विकल्प चुन सकते हैं –

ए. सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना।

बी. अंशदायी भविष्य निधि-सह-ग्रेच्युटी योजना जिसमें भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के वेतन के 8 प्रतिशत तक सीमित होगा।

ग. केवल अंशदायी भविष्य निधि, जिसमें नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत होगा।

नियम और शर्तें

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
2. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
3. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
4. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

“5. उन कर्मचारियों के मामले में जो 1 अप्रैल, 1972 को या उसके बाद विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन कानून के

अनुच्छेद (4) के तहत अपने विकल्प का प्रयोग करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका परिवार योजना के बीच के विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि यदि परिवार योजना में दी गई योजना का विकल्प चुनता है।

ए. इसे मृतक कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के विश्वविद्यालय के हिस्से को, उस पर ब्याज के साथ या तो नकद में या उपदान की राशि या दोनों में से समायोजन करके, और नियोक्ता के हिस्से को नकद में मृतक की अंशदायी भविष्य निधि में, जो उस पर ब्याज के साथ मृतक के वेतन के 8 प्रतिशत से अधिक है, वापस करना होगा, लेकिन फिर वे पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।

6. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

भवदीय,
पंजीयक,
एस.के. विश्वविद्यालय
दुमका "

5. योजना के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि एक कर्मचारी, जिसने विकल्प का उपयोग नहीं किया है और 1.4.1972 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ है, लेकिन विकल्प का उपयोग करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है, परिवार को भविष्य निधि योजना के तहत नए विकल्प का उपयोग करने का अवसर दिया गया है, बशर्ते ब्याज के साथ उपदान की राशि के समायोजन के लिए योजना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो। अपीलार्थी ने रिट न्यायालय के समक्ष उक्त योजना के लाभ के लिए प्रार्थना की थी, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा "एक और मौका" और "एक नया विकल्प" अभिव्यक्ति की गलत तरीके से व्याख्या करते हुए बढ़ाया गया था। "एक और अवसर" के रूप में "एक नए विकल्प" का प्रयोग करने का उक्त अवसर नियम और शर्तों के अधीन था, जैसा कि योजना दिनांक 30.7.1998 में निर्दिष्ट किया गया था। योजना की शर्त संख्या 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, उसकी 1.4.1972 को या उसके बाद अपने विकल्प का उपयोग करने से पहले मृत्यु हो गई है, तो उसका परिवार नए विकल्प

का उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जिससे उन्हें नियमों और शर्तों के अधीन एक और मौका मिलेगा।

6. वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी के पति ने अपनी मृत्यु से पहले ही विकल्प का उपयोग कर लिया था। प्रचलित योजना के तहत उपयोग किए जाने वाले विकल्प के संदर्भ में सभी लाभ परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। उक्त आकस्मिकता में, योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार, अपीलार्थी को फिर से विकल्प का उपयोग करने के लिए एक और अवसर का लाभ उठाने के लिए एक नए विकल्प का उपयोग करने का अधिकार नहीं था। विवादित आदेश द्वारा, खंड पीठ ने योजना के खंड 5 की सही व्याख्या की है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को सही रूप से अपास्त किया है। हमारे विचार में, खंड पीठ ने चुनौती के तहत आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, इस अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. तदनुसार, इस याचिका को खारिज किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।